पटना में दिनांक–28 अक्टूबर, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	उद्योग विभाग	
1.	मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, गलगलिया चेक पोस्ट, ठाकुरगंज, किशनगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।	1. **स्वीकृत।**
	उद्योग विभाग	
2.	बिहार बायो–फ्यूल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।	2. **स्वीकृत।**
	उद्योग विभाग	
3.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली, 2026 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	3. **स्वीकृत।**
	उद्योग विभाग	
4.	"बिहार एम०एस०एम०ई० नीति 2026" की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	4. **स्वीकृत।**
	उद्योग विभाग	
5.	उद्योग विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–4773 दिनांक–28.10.2013 तथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक–1581 दिनांक–18.05.2026 द्वारा निर्गत "मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कलस्टर विकास योजना" को अधिक्रमित करते हुए "मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कलस्टर विकास योजना (CM-CDP) 2026" की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	5. **स्वीकृत।**
	उद्योग विभाग	
6.	मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनिरीज प्रा० लि०, राजापट्टी, बैकुंठपुर, गोपालगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।	6. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

7. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कार्यरत ग्रिड उपकेन्द्र दरभंगा एवं खगौल में 02 अदद् 200 एम०वी०ए० पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने हेतु कुल 33.44 करोड़ (तैंतीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

8. राज्य की वितरण कंपनियों के क्षेत्राधीन एल०टी० प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, एल०टी० केबल एवं अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों इत्यादि के क्षमता विस्तार हेतु चरणवार तरीके से अधिकतम तीन वर्षों में कुल 11,096.55 करोड़ (ग्यारह हजार छियानवे करोड़ पचपन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की गारंटी पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 6,066.00 करोड़ (छः हजार छियासठ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 5,030.55 करोड़ (पाँच हजार तीस करोड़ पचपन लाख) रूपये को विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बैंको से वित्तीय पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने, ऋण स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

कृषि विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन–बीज घटक (कृषोन्नति योजना) के अन्तर्गत बीज गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ीकरण, बीज अवसंरचना का निर्माण एवं आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय बीज भंडारण कार्य के तहत कुल 1182.588 लाख (ग्यारह करोड़ बयासी लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

खेल विभाग

10. बिहार राज्य खेल–2026 के आयोजन हेतु राशि प्रदान करने के निमित्त बिहार ओलंपिक संघ (Bihar Olympic Association) को बिहार वित्त नियमावली यथासंशोधित 2024 के नियम–131 ZZ के आलोक में नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने एवं उक्त आयोजन पर व्यय होने वाली राशि ₹12,00,00,000/–(बारह करोड़ रूपये) मात्र बिहार ओलंपिक संघ (Bihar Olympic Association) को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

10. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

11. बिहार राज्य में बढ़ती जनसंख्या एवं अपराध के दृष्टिकोण से मोतिहारी, पूर्णियाँ एवं सारण जिला में नगर पुलिस अधीक्षक (स्टाफ ऑफिसर कोटि) के 03 (तीन) पदों सहित उनके कार्यालय के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल–12 (बारह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 11. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

12. भागलपुर जिला में पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, भागलपुर के मूल पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी–1, विधि–व्यवस्था, भागलपुर के रूप में पुनर्गठित करने एवं बिहार पुलिस मुख्यालय हेतु सृजित पुलिस उपाधीक्षक के 4 पदों में से 1 पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी–2, विधि–व्यवस्था, भागलपुर के रूप में प्रत्यावर्तित करने के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

13. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के विस्तार एवं क्षमतावर्धन हेतु क्षेत्रीय आर्थिक अपराध इकाईयों के निमित्त 143 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

14. बिहार राज्य के फॉरेंसिक कार्यालयों को पुलिस नियंत्रण से मुक्त करते हुए गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्रियाशील रखे जाने के लिए निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–9501 दिनांक–03.08.2026 के आलोक में सभी फॉरेंसिक कार्यालयों के लिए निदेशालय की संरचना के गठन के उद्देश्य से निदेशक प्रमुख के पूर्व से सृजित एकल अस्थायी पद को प्रत्यर्पित करते हुए एकल स्थायी पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

15. नवादा जिलान्तर्गत अंचल–वारिसलीगंज, मौजा–मकनपुर, में नयी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (By-products) आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि० (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. "सोनपुर आयोजना क्षेत्र" के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय–विक्रय/हस्तांतरण पर अधिरोपित प्रतिबंध को हटाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. विश्वामित्र पथ (बक्सर–आरा–मनेर पथ, लंबाई–90 कि०मी०), गंगा अम्बिका पथ (बिदुपुर–दिघवारा–उत्तरी गंगा पथ, लंबाई–56 कि०मी०) तथा नारायणी पथ (दरिहारा (कोन्हुआ)–डुमरिया घाट, गोपालगंज, लंबाई–73.51 कि०मी०) पथ हेतु ट्रांजेक्शन एडवाईजर (टी०ए०) के रूप में परामर्शी सेवाओं हेतु कुल राशि ₹3710.00 लाख (रूपये सैतीस करोड़ दस लाख) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. विश्वामित्र पथ (बक्सर–आरा–मनेर गंगा पथ, लंबाई 90 कि०मी०) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०), भूमि अधिग्रहण, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियाँ एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के निमित कुल 260.00 लाख (रूपये दो करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20. नारायणी पथ (दरिहारा (कोन्हुआ)–डुमरिया घाट, गोपालगंज, पथ (लंबाई–73.51 कि०मी०) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०), भूमि अधिग्रहण, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियाँ एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु परामर्शी सेवा हेतु कुल राशि ₹210.00 लाख (रूपये दो करोड़ दस लाख) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21. पटना, बिहार में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर के विकास के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कार्य हेतु कुल राशि 1821.00 लाख (अठारह करोड़ इक्कीस लाख) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22. पथ प्रमंडल भागलपुर अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा पथ के कि०मी० 0.00 से 8.350 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 6868.79 लाख (रूपये अड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल–अररिया नई रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु अंचल–पिपरा के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल प्रस्तावित रकवा–3.12725 एकड़ कैसरे हिन्द एवं सड़क, बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) सशुल्क आधार पर कुल राशि–66,97,883/–(छियासठ लाख सन्तानवे हजार आठ सौ तिरासी रूपये) मात्र के भुगतान पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल–अररिया नई रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु अंचल–त्रिवेणीगंज एवं पिपरा के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकवा का योगफल–21.48068 एकड़ बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) सशुल्क आधार पर कुल राशि–4,22,38,737/– (चार करोड़ बाईस लाख अड़तीस हजार सात सौ सैंतीस रूपये) मात्र के भुगतान पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

26. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र–छात्राओं हेतु निजी भवनों में छात्रावास की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रति छात्र/प्रति बेड रू० 1000.00 मात्र के आधार पर वर्तमान में नामांकित कुल 49,000 छात्र–छात्राओं के लिए प्रति माह कुल संभावित रू० 4,90,00,000.00 (चार करोड़ नब्बे लाख रूपये) मात्र तथा वार्षिक व्यय कुल रू० 58,80,00,000.00 (अन्ठावन करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

26. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

27. आम नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं इससे संबंधित जानकारी **WhatsApp** के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०–131ज्ञ(त) के तहत नामांकन के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड (**BSNL**) का चयन तथा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रू० 2,34,00,000.00 (दो करोड़ चौंतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

27. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

28. बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी–2026 की स्वीकृति।

28. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. रोहतास जिलान्तर्गत अंचल–सासाराम, मौजा–बेलाढ़ी, थाना सं०–107, खाता सं०–245, खेसरा सं०–1215 की कुल प्रस्तावित रकवा–28 डी० अनावाद सर्वासाधारण की भूमि एस०आई०बी० के कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–63,00,000/– (तिरेसठ लाख रूपये) मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

29. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

30. डा० उमेश प्रधान, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि–30.11.2026 के उपरान्त इन्हें राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना में अगले 02 (दो) वर्ष के लिए संविदा विस्तार किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

30. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

31. सहरसा हवाई पट्टी (एयरस्ट्रिप) की 1000 वर्ग मीटर भूमि मेसर्स जी.आर.डी. एयर एकेडमी प्रा. लि. को उड़ान प्रशिक्षण संगठन एवं संबंधित गतिविधियों की स्थापना हेतु नामांकन के आधार पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित किए जाने एवं संबंधित आनुषंगिक निर्णयों के संबंध में।

31. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

32. भारत सरकार एवं बिहार सरकार के बीच हुए उड़ान योजना अंतर्गत समझौता ज्ञापन (**MoU**) के आलोक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अंतर व्यवहार्यता निधि (**VGF**) के रूप में मई–2026 से सितम्बर–2028 तक मासिक 1.5 करोड़ की दर से कुल 29 माह का अनुमानित व्ययगत राशि कुल ₹43,50,00,000/– (तेंतालीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 32. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

33. बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 01 (एक) अतिरिक्त पद का अगले आदेश तक के लिए सृजन के संबंध में। 33. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

34. बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति। 34. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

35. बिहार प्रशासनिक सेवा के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन किये जाने के संबंध में। 35. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

36. मधुबनी न्यायमंडल में NDPS Act. के अंतर्गत दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 36. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

37. पटना न्यायमंडल में एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक वादों के निष्पादन के लिए मुख्यालय में जिला न्यायाधीश स्तर के दो अतिरिक्त न्यायालयों को अनन्य वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करने के निमित्त जिला न्यायाधीश स्तर के एक–एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 37. **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

38. बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाई–मोतीपुर की 151.58 एकड़ भूमि पर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में। 38. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

39. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के साथ एम०ओ०यू० के माध्यम से गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों–कोसी, गंडक एवं सोन का फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन कार्य हेतु राशि ₹1,99,42,000.00 (एक करोड़ निन्यानबे लाख बयालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

39. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

40. राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा अधिनयम, 2021 के अंतर्गत बिहार में निर्दिष्ट बाँधों (कुल 24 अदद) की वास्तविक स्थिति के आकलन एवं सुरक्षा के लिए गाद अध्ययन, रिवाइज्ड डिजाइन फ्लड का आकलन, आपातकालीन कार्य योजना (ई०ए०पी०) तथा संचालन एवं रखरखाव (ओ० एंड एम०) मैनुअल तैयार करने हेतु प्राक्कलित राशि रू० 8,39,32,936/– (आठ करोड़ उन्नचालीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ छत्तीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

40. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

41. बांका जिला अंतर्गत बदुआ नदी के किनारे तेलडीहा दुर्गा मंदिर के निकट चेक डैम सहित पाथवे का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि रू० 3709.00 लाख (रू० सैंतीस करोड़ नौ लाख मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के सबंध में।

41. स्वीकृत।

गृह विभाग

42. प्रक्षेत्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रक्षेत्रीय कार्यालय हेतु 04 पदों को स्थानान्तरित किए जाने एवं कार्यालय के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कोटि के कुल–20 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

42. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

43. पशु आहार हेतु छोआ तथा बायोडीजल एवं फॉर्मलडीहाइड निर्माण हेतु मेथनॉल का राज्य के बाहर से आयात हेतु स्वीकृति के संबंध में।

43. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

44. बिहार राज्य के बाहर औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्त्ति किये जाने वाले इथनॉल में भारतीय मानक IS 4117:2008 के अनुरूप अनुलग्नक–8 संकल्प प्रारूपानुसार कुल 12 (बारह) विकारकों के मिश्रण हेतु स्वीकृति के संबंध में।

44. स्वीकृत।